भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2139
05.08.2024 को उत्तर के लिए

एनएएफसीसी के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति

2139. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) के अंतर्गत वित्तपोषित विशिष्ट परियोजनाओं अथवा पहलों का ब्यौरा क्या है जिनका उद्देश्य हाल के लू के प्रभाव को कम करना है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान विशाखापट्टनम जिले सहित आंध्र प्रदेश में लू प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं के लिए एनएएफसीसी के अंतर्गत वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई;

(ग) ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और निधि के उपयोग तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई चुनौती आ रही है अथवा कुछ विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में विशेष रूप से लू से निपटने के उद्देश्य से एनएएफसीसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) की स्थापना भारत के उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन संबंधी कार्यकलापों में सहयोग प्रदान करने हेतु किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। एनएएफसीसी को प्रोजेक्ट मोड की भांति कार्यान्वित किया गया है और आंध्र प्रदेश सहित 27 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 847.48 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 30 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एनएएफसीसी के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन निकाय (एनआईई) है और नाबार्ड को परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन तथा एनएएफसीसी के दिशानिर्देशों के आधार पर किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। नवंबर, 2022 में एनएएफसीसी को एक गैर-स्कीम बनाया गया है।

एनएएफसीसी के तहत विशाखापट्टनम में कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई है। तथापि, अगस्त, 2016 में ''आंध्र प्रदेश के तटीय एवं शुष्क क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल कार्यकलाप'' नामक एनएएफसीसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी और उसे आंध्र प्रदेश के तीन जिलों नामत: अनंतपुरम (अनथपुर), श्री पोट्टि श्रीरामुलु नेल्लोर (नेल्लोर) और विजयनगरम (विजियानगरम) में कार्यान्वित किया गया है। परियोजना घटकों में से एक घटक डेयरी पुशओं पर गर्मी और चक्रवातों के प्रभावों को प्रबंधित करने हेतु समुदाय आधारित उत्तम पद्धतियों की स्थापना करना है। आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित एनएएफसीसी परियोजना का वित्तीय विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	धनराशि (रुपए)
स्वीकृत धनराशि	12,71,36,316/- (स्वीकृति की तिथि : 16-08-2016)
नाबार्ड को जारी धनराशि	6,35,68,108/- (प्राप्ति की तिथि : 26-10-2016)
नाबार्ड द्वारा कार्य-निष्पादन निकाय (ईई) को जारी धनराशि	5,12,78,000/- (संवितरण की तिथि : 11-08-2017)
ईई के स्तर पर उपयोग	228,49,000/-

इस परियोजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों में भूमि की पहचान में देरी होना और उसे पृथक करना, सिविल अभियांत्रिकी कार्यकारी और तकनीकी संसाधन एजेंसियों की पहचान करना, पशुओं के लिए जलवायु अनुकूल आश्रय स्थल की रूप-रेखा को अंतिम रूप देना शामिल है।

*****